EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan
Useful For Prelims
Date: 19 January 2026

कुछ अलग | सशक्त महिला समृद्ध बिहार नाम की किताब में छपी कहानी, इसमें हर जिले की महिला उद्यमी शामिल

लखपति जीविका दीदियों का संघर्ष जानेगी दुनिया

पटना, मुख्य संवाददाता। गांव में रहकर अपने हुनर को रोजगार का माध्यम बनाया। सामान्य ग्रामीण महिला से उद्यमी बनीं। आज लाखों रुपये कमा रही हैं। अब ये जीविका दीदी लखपति दीदी के तौर पर पहचान बना रही हैं। इनके संघर्ष की कहानी पर किताबें छपी हैं। इस किताब को अब जीविका के तमाम समूहों के पास भेजा जाएगा। इससे अन्य जीविका दीदियां भी प्रेरित होंगी। जीविका की ओर से दीदियों के संघर्ष की कहानी अबतक ऑनलाइन बुकलेट के रूप में छापी जाती थी। लेकिन, पहली बार राज्यभर की 52 लखपति दीदियों के संघर्ष को किताब का रूप दिया गया है। इसमें उनकी शुरुआत से लेकर उद्यमी और लखपति बनने तक की बातें बताई गयी हैं। ऑनलाइन में जहां पांच से छह जीविका दीदियों की कहानी को शामिल किया जाता था, वहीं सशक्त महिला समृद्ध बिहार नाम की किताब में 52 जीविका दीदियों को शामिल किया गया है। किताब में हर जिले की लखपति दीदियों को शामिल किया गया है। जीविका दीदी को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है।

52 लखपति जीविका दीदियों की कहानी किताब में प्रकाशित

"ग्रामीण महिलाओं के संघर्ष को जानकर अन्य को भी आगे बढ़ाया जाये, इस मकसद से यह किताब छापी गयी है। इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा। इसमें ऐसी दीदियों को शामिल किया गया है जो खुद की मेहनत से आगे बढ़ी। – **हिमांशु शर्मा**, सीईओ जीविका

नजीर 1 शाहकुंड प्रखंड भागलपुर की झुना देवी मजदूरी करके परिवार चलाती थी। आज वो गांव की अग्रणी महिला उद्यमी है। वर्ष 2017 में जीविका से जुड़कर नमकीन बनाने का काम शुरू किया। लोन लेकर मशीन खरीदी। इससे रोजाना पांच से छह हजार पैकेट तैयार कर लेती है। आज सालाना आय दस लाख रुपये है।

नजीर 2 पुनपुन की चंपा देवी खेतीबाड़ी करती थी। जीविका से जुड़ 15 हजार का लोन लिया। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ली। आज खेतों में ड्रोन से खाद-बीज का छिड़काव करती है। ड्रोन दीदी के नाम से मशहूर चंपा विलेज रिसोर्स पर्सन के नाम से जानी जाती है। कमाई आठ लाख सालाना है।

फ्रांस ने सौमित्र चटर्जी को दिया था सर्वोच्च नागरिक सम्मान

बंगाली सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता सौमित्र चटर्जी का जन्म 1935 में आज के ही दिन कलकत्ता (अब कोलकाता) में हुआ था। आल इंडिया रेडिया में अनाउंसर के तौर पर करियर की शुरुआत की। 1955 में सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार से फिल्मों में कदम रखा। सत्यजीत रे के साथ 14 फिल्मों में काम किया। उन्होंने छह दशक में 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें पद्म भूषण, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2018 में फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी आनर दिया। 15 नवंबर, 2020 को सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया।

Sci & Tech

Hindustan Page
Dainik Bhaskar
Jansatta Page

गलती स्वीकारने में है सच्ची महानता

अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन का यह प्रसंग उनकी ईमानदारी और विनम्रता को उजागर करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान कद से नहीं, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा से पहचाना जाता है।

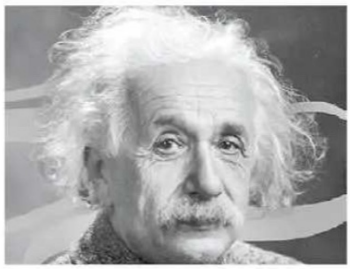

1915 में आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धान्त दिया। 1917 में वे इस सिद्धान्त पर आगे काम कर रहे थे और ऐसा समीकरण प्रतिपादित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें ब्रह्मांड को स्थिर माना जाए। ब्रह्मांड, जो स्थिर हो और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समाप्त न हो जाए। अपनी गणना को संतुलित करने के लिए उन्होंने 'कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट' की धारणा को शामिल किया।

आइंस्टीन ने कहा कि यह बल गुरुत्वाकर्षण के विरोध में काम करता है। लेकिन 12 साल बाद अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने अपने अध्ययन के जरिए यह साबित किया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि निरंतर फैल रहा है। यह खोज आइंस्टीन के 'कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट' के विपरीत थी। आइंस्टीन हबल की नई खोज के परिपेक्ष्य में अपने सिद्धान्त को फिर से जांचने लगे। कुछ समय बाद उनको लगा कि उनका अनुमान गलत था। आइंस्टीन ने इसे छुपाने के बजाय सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट को जोड़ना उनके जीवन की 'सबसे बड़ी भूल' थी। एक ऐसे वैज्ञानिक के लिए, जिसकी प्रतिष्ठा पहले ही स्थापित हो चुकी थी– ऐसी स्वीकारोक्ति असाधारण साहस का परिचायक थी। आइंस्टीन ने दिखाया कि महानता अपनी बात पर अड़े रहने में नहीं, बल्कि नई सच्चाई के सामने स्वयं को सुधारने में है।

और अब महसूस हुआ ऐसा बल

आइंस्टीन के प्रेक्षण के कई दशकों बाद 1998 से 2007 के बीच वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों में एक ऐसे ही बल का पता लगाया, जो आइंस्टीन के 'कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट' से मिलता–जुलता है। इसे डार्क एनर्जी नाम दिया गया है। वैज्ञानिक अब इस डार्क एनर्जी को पूरी तरह से साबित करने में जुटे हुए हैं। • **1 मिनट रीड**

पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम का किया गया प्रयोग

1883 में आज ही के दिन अमेरिका में थामस अल्वा एडिसन द्वारा बनाए गए पहले इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। एडिसन ने कई तारों के माध्यम से एक ही जगह से बिजली प्रवाहित करते हुए न्यूजर्सी के रोशली क्षेत्र को रोशन किया था। इस खोज का असर पूरी दुनिया पर पड़ा।

दुनिया के सामने आया पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस

1986 में आज ही पहली बार पर्सनल कंप्यूटर के लिए तैयार किए गए वायरस से विज्ञानियों का सामना हुआ था। यह फ्लापी डिस्क को प्रभावित करता था। पाकिस्तान के दो भाइयों द्वारा तैयार किए गए इस वायरस को ब्रेन नाम दिया गया। यह डाटा को खराब नहीं करता था, बस उसे कापी नहीं करने देता था।

जागरण विशेष

प्रकृति व विज्ञान के संगम से किसान समृद्ध एवं समाज होगा स्वस्थ

मिट्टी, पौधे और सूक्ष्मजीवों की प्राकृतिक शक्ति को समझकर विज्ञानी दिखा रहे खेती का नया माडल

शैलेश अस्थान • जागरण

वाराणसी : वाराणसी के शाहंशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (आइआइवीआर) में इन दिनों खेती को देखने और समझने का नजरिया बदल रहा है। यहां विज्ञानी यह साबित करने में जुटे हैं कि खेती केवल रसायनों और कीटनाशकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि प्रकृति के भीतर मौजूद अद्भुत शक्ति को समझकर किसान न सिर्फ अधिक उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि मिट्टी, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं। यही सोच भारत को एक नए कृषि युग की दहलीज पर ले जा रही है।

आइआइवीआर में हो रहा शोध मल्टीओमिक्स जैसे आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। इसके जरिये पौधों के जीन, प्रोटीन और उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्राकृतिक रसायनों को समझा जा रहा है। यह विज्ञान बताता है कि पौधे सूखा, अधिक तापमान, लवणीयता और रोगों जैसे तनावों का सामना कैसे करते हैं। इसी समझ के आधार पर ऐसी तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे फसलें संकट आने से पहले ही मजबूत बन सकें।

संस्थान के निदेशक डा. राजेश कुमार बताते हैं कि आज किसान कई मोर्चों पर जूझ रहा है। मिट्टी की उर्वरता घट रही है, मौसम का मिजाज अनिश्चित हो गया है और खाद व कीटनाशकों की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में खेती को टिकाऊ बनाने के लिए प्रकृति आधारित समाधान जरूरी हैं। मेटाबोलोमिक्स के माध्यम से यह जाना जा रहा है कि तनाव की स्थिति में पौधे फेनोलिक्स, फ्लेवोनोइड्स, अमीनो एसिड, फाइटोहार्मोन और विटामिन जैसे उपयोगी यौगिक कैसे बनाते हैं। इन्हीं के आधार पर जैव उत्तेजक तैयार किए जा रहे हैं, जो फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और पैदावार को सुरक्षित रखते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी के प्रधान विज्ञानी डा. डीपी सिंह बताते हैं कि मिट्टी के भीतर मौजूद सूक्ष्मजीव खेती के असली नायक हैं। ये सूक्ष्मजीव पौधों को पोषण देने के साथ उन्हें रोगों से बचाने में भी मदद करते हैं। मल्टीओमिक्स की सहायता से यह पहचाना जा रहा है कि एजोटोबैक्टर, बैसिलस और प्सीयुडोमोनास जैसे जीवाणु किन परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। अब इन्हें अकेले नहीं, बल्कि संतुलित मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

इन मिश्रित जीवाणु अनुकल्पों, जैसे बीसी-6 और एजोबीसी, के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत 25 से 30 प्रतिशत तक घटाने में सफलता मिली है। इससे न केवल लागत कम हो रही है, बल्कि वर्षों से रसायनों के कारण कमजोर हुई मिट्टी भी धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही है। यह बदलाव खेती को फिर से प्रकृति के करीब ला रहा है।

कम रसायन, कम लागत और बेहतर गुणवत्ता से किसान समृद्ध होंगे। जब किसान समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। दूसरा, लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी तो समाज स्वस्थ बनेगा।

एआइ की भूमिका भी अहम : डा. डीपी सिंह

डा. डीपी सिंह

जैव प्रौद्योगिकी के प्रधान विज्ञानी डा. डीपी सिंह बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ की भूमिका भी अहम है। लाखों शोध आंकड़ों का विश्लेषण कर एआइ की मदद से हर क्षेत्र की स्थानीय मिट्टी, जलवायु और फसल की जरूरत के अनुसार अलग-अलग जैव-फार्मूले तैयार किए जा रहे हैं। यानी अब खेती में 'एक ही समाधान सबके लिए' की सोच टूट रही है और हर किसान के लिए व्यक्तिगत समाधान संभव हो रहा है। इसका सीधा लाभ किसान की आय, उपभोक्ता के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा।

प्रयोगशाला में पौधों के हार्मोंस, अणुओं आदि पर शोध करते विद्यार्थी • आइआइवीआर

यह नया विज्ञान, जैविक उत्पादों पर भरोसा बढ़ाएगा और खेती को व्यावहारिक, समावेशी और टिकाऊ बनाएगा। देश की खेती अब सिर्फ उत्पादन की दौड़ में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। इसमें विज्ञान एवं प्रकृति साथ मिलकर किसानों को सशक्त बना रहे हैं।

डा. राजेश कुमार, निदेशक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

BIHAR

Dainik Jagaran Page

Hindustan Page

हैदराबाद में गूंजा बिहार के विकास का संकल्प

- लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में एक हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए
- हैदराबाद के टी-हब में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 का हुआ आयोजन
- विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए पुरस्कार दिए गए

पटना, कार्यालय संवाददाता। लेट्स इंस्पायर बिहार (एलआईबी) अभियान ने रविवार को टी-हब, हैदराबाद में बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 का सफल आयोजन किया। सम्मेलन में एक हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों, उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, पेशेवरों, सामाजिक चिंतकों व देशभर से आए बिहारी प्रवासी समुदाय ने भाग लिया। सभी ने मिलकर बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया।

उद्घाटन तेलंगाना के मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ईटिला राजेंद्र ने किया। उद्घाटन सत्र में लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक आईपीएस विकास वैभव, विधायक मिथिलेश तिवारी, पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा, डेहरी विधायक राजीव रंजन सिंह, बेगूसराय से पूर्व विधायक ललन कुंवर आदि रहे।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का वीडियो संदेश भी सुनाया गया। उन्होंने आयोजन की सराहना की। हैदराबाद के लोगों, विशेषकर बिहारी प्रवासी समुदाय से बड़ी संख्या में भागीदारी करने व लेट्स इंस्पायर बिहार आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया।

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार की दीर्घकालिक समृद्धि के लिए राज्य में उद्योगों, स्टार्ट-अप्स एवं कौशल-आधारित रोजगार का सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना आवश्यक है।

रत्नेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में आधारभूत संरचना एवं सुशासन में निरंतर सुधार हो रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार राज्य के प्रति धारणा बदलने एवं निवेश एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। इससे युवाओं की बड़ी भूमिका है।

बाधाओं या असफलताओं से नहीं डरने का किया आह्वान

विकास वैभव ने कहा कि नवाचार एवं उद्यमिता के लिए विश्व प्रसिद्ध इस शहर से बिहार के भविष्य पर चर्चा करना उनके लिए विशेष रूप से अर्थपूर्ण है। उन्होंने उद्यमियों एवं युवाओं से आह्वान किया कि वे बाधाओं या असफलताओं से न डरें। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि कहा कि भारत के किसी भी शहर या राज्य में जहां विकास हुआ है, वहां बिहार और बिहारी समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य रहा है। उन्होंने बिहार की गौरवशाली सभ्यतागत विरासत को रेखांकित किया। मौके पर स्कूल प्राइवेट स्कूल ऐसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद रहे। शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए।

सुविधा • बैक्टीरिया और फंगस मुक्त होने से आम, मखाना, आलू और लीची का निर्यात होगा

बिहटा में ई-रेडिएशन सेंटर खुला, कृषि उत्पाद एक साल तक खराब नहीं होंगे

सिटी रिपोर्टर | पटना

बिहार से कृषि उत्पादों के निर्यात में अब दिक्कत नहीं होगी। विदेश भेजने से पहले बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त करना पड़ता है। पटना के बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया में ई-रेडिएशन सेंटर स्थापित किया गया है। पांच एकड़ जमीन पर स्थापित इस सेंटर में पैक हाउस से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक की व्यवस्था की गई है। बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त करने के बाद कृषि उत्पादों को यहां तीन से छह महीने तक संरक्षित किया जा सकेगा। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और बिहार का पहला ई-रेडिएशन सेंटर है। खाद्य पदार्थों को गामा रे की मदद से संरक्षित किया जाता है। सेंटर के संचालक विकास कुमार ने बताया कि इस साल बैक्टेरिया और फंगस मुक्त आम, मखाना, आलू और लीची का निर्यात होगा।

अब सालभर सुरक्षित रहेगा मखाना

दो महीने में 60 टन मखाना को संरक्षित कर उसकी लाइफ एक साल तक बढ़ा दी गई। पहले मखाना तीन-चार महीने ही सुरक्षित रह पाता था। चार माह होते ही कीड़े पड़ जाते थे, जिससे विदेशों में निर्यात के समय रिजेक्शन बढ़ जाता था। हर साल 20-30 प्रतिशत मखाना हर साल रिजेक्ट हो जाता था। इससे मखाना उत्पादकों से लेकर निर्यातकों तक को भारी नुकसान झेलना पड़ता था।

क्या है ई-रेडिएशन सेंटर : ई-रेडिएशन सेंटर कृषि उत्पादों, मसालों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को विकिरण तकनीक का उपयोग करके प्रोसेस करता है, जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ती है, शेल्फ लाइफ लंबी होती है और वे अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा करते हैं। इसमें गामा किरणों या इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग होता है, साथ ही कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग जैसी सुविधाएं भी होती हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित, नियंत्रित मात्रा में गामा किरणों या इलेक्ट्रॉन बीम के संपर्क में लाया जाता है, जो बैक्टीरिया, कीड़े और फफूंद को खत्म करते हैं।

बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में अररिया बना नंबर-1 जिला, सीमावर्ती जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा

परिवार नियोजन और आधुनिक सेवाओं में बढ़ रही जागरुकता

भास्कर न्यूज | पटना

बिहार स्वास्थ्य रैंकिंग में बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए दूरदराज और सीमावर्ती जिलों ने मिसाल कायम की है। स्वास्थ्य विभाग की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में अररिया जिला 69.42 स्कोर के साथ पूरे बिहार में पहले नंबर पर रहा। खगड़िया (67.10) दूसरे, शिवहर (63.38) तीसरे और वैशाली (62.34) चौथे स्थान पर रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस रैंकिंग से पता चलता है कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद सीमावर्ती जिलों ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में गंभीरता दिखाई है। बुनियादी ढांचे के संचालन में अररिया, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और जमुई ने रिकॉर्ड बनाया है। इन जिलों ने सभी लक्षित स्वास्थ्य केंद्रों को 100 प्रतिशत संचालित करने की उपलब्धि हासिल की है। इसका सीधा लाभ ग्रामीण आबादी को मिल रहा है, जिन्हें अब छोटी बीमारियों के लिए जिला मुख्यालय नहीं दौड़ना पड़ता।

रिपोर्ट के मुताबिक अररिया ने परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी 69 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की है। प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन के साधनों जैसे पीपीआईयूसीडी को अपनाने में रोहतास ने 40 प्रतिशत और मुंगेर ने 39 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है। परिवार नियोजन के आधुनिक इंजेक्शन 'अंतरा' की खुराक सुनिश्चित करने में शिवहर 2.3 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ राज्य में सबसे आगे है।

आदेश : राज्य के मंत्रियों और सचिवों को जिलों का प्रभार मिला

सम्राट पटना के प्रभारी मंत्री 11 को दो-दो जिले का जिम्मा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्री सह कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तय कर दी है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना तथा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर और भोजपुर का जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 25 मंत्रियों के बीच 38 जिलों का प्रभार बंटा है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को अलग-अलग जिलों के प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय ने रविवार को इसका आदेश जारी किया। मंत्रियों पर योजनाओं-कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और समीक्षा के साथ ही इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने की जिम्मेवारी होगीष साथ ही वे स्थानीय समस्याओं के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराएंगे। कई मंत्रियों को दो-दो जिला तथा ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को तीन जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

कई मंत्रियों के जिले की जिम्मेदारी बदली: कई मंत्रियों को इस बार जिले की जिम्मेदारी बदल दी गई है। वहीं, कइयों को दो जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले 25 अप्रैल, 2025 को जिला प्रभारी मंत्री बनाया गया था, तब 35 मंत्री थे। इस बार 25 मंत्री हैं। पहले विजय सिन्हा मुजफ्फपुर के प्रभार में थे, इस बार भोजपुर की भी जिम्मेदारी मिली है। विजय कुमार चौधरी के पास पूर्णिया और नालंदा के अलावा पूर्वी चंपारण की जिम्मेदारी मिली है। अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और जहानाबाद के अलावा शिवहर का भी प्रभारी बनाया गया है। मंगल पांडेय को दरभंगा की जिम्मेदारी थी, जिन्हें अब पश्चिम चंपारण का प्रभार भी दिया गया है। श्रवण कुमार को मधेपुरा की जगह पूर्णिया की जिम्मेदारी मिली है। बिजेंद्र प्रसाद यादव वैशाली और सारण के प्रभारी मंत्री बने हैं।

➤ पढ़िए राजकाज

योजनाओं की समीक्षा और क्रियान्वयन में तेजी की पहल

सम्राट चौधरी, प्रभारी मंत्री पटना | विजय सिन्हा, प्रभारी मंत्री भोजपुर और मुजफ्फरपुर

03 जिले सीतामढ़ी, शिवहर और जहानाबाद के प्रभारी बने ग्रामीण कार्य के मंत्री अशोक चौधरी

किसे कौन से जिले का प्रभारी बनाया गया

विजय सिन्हा, उपमुख्यमंत्री	मुजफ्फरपुर और भोजपुर
विजय चौधरी, जल संसाधन	पूर्वी चंपारण, नालंदा
बिजेंद्र प्रसाद यादव, ऊर्जा मंत्री	वैशाली और सारण
श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास	समस्तीपुर और पूर्णिया
मंगल पांडेय, स्वास्थ्य	दरभंगा और पश्चिम चंपारण
डॉ. दिलीप जायसवाल, उद्योग	भागलपुर और गयाजी
लेशी सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	मधुबनी-मधेपुरा
मदन सहनी, समाज कल्याण	सुपौल और खगड़िया
सुनील कुमार, शिक्षा	रोहतास और लखीसराय
जमा खान, अल्पसंख्यक कल्याण	किशनगंज-शेखपुरा
डॉ. प्रमोद कुमार, सहकारिता	सहरसा और सीवान

इन मंत्रियों को एक जिले का जिम्मा

सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री	पटना
संजय टाइगर, श्रम संसाधन	बांका
अरुण शंकर प्रसाद, पर्यटन	बेगूसराय
सुरेंद्र मेहता, डेयरी मत्य एवं पशु	कटिहार
नारायण प्रसाद, आपदा प्रबंधन	गोपालगंज
रमा निषाद, पिछड़ा अतिपिछड़ा कल्याण	बक्सर
लखेंद्र कुमार रौशन, एससी-एसटी कल्याण	अररिया
श्रेयसी सिंह, खेल एवं आईटी	नवादा
संजय कुमार, गन्ना उद्योग	मुंगेर
संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	जमुई
दीपक प्रकाश, पंचायती राज	अरवल
रामकृपाल यादव, कृषि	कैमूर
संतोष कुमार सुमन, लघु जल संसाधन	औरंगाबाद

भास्कर एक्सक्लूसिव 18-24 महीने की डेडलाइन, 25 नई मिल भी खुलेंगी

30 साल बाद खुलेंगी 7 चीनी मिलें, 2 लाख युवाओं को नौकरी-रोजगार

अमनेश दुबे | पटना

राज्य में तीन दशकों से बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में बंद 7 चीनी मिल खुलेंगी। इन्हें शुरू करने का डेडलाइन 18 महीने से 24 महीने तक रखा गया है। इनके शुरू होने से करीब 2 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलने का पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। राज्य सरकार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली घोषणा में चीनी मिलों का विशेष योगदान होगा। पहले चरण में मिलें खुलने के बाद 25 नई मिलें भी खोली जाएंगी। इनमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण क्षेत्र की प्रमुख मिलें शामिल हैं।

वो सबकुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है

जरूरत क्यों? सरकार ने 5 सालों में राज्य में 1 करोड़ नौकरी-रोजगार का लक्ष्य रखा है। सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसे में बंद चीनी मिलों को खोलने से इसमें सहयोग मिलेगा।

फायदा क्या? लाखों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्हें अपनी उपज के लिए स्थानीय बाजार मिलेगा और समय पर भुगतान की समस्या भी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

रीगा मॉडल? रीगा चीनी मिल खुलने से बेहतर रिजल्ट आया है। इसके बाद बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने की दिशा में तैयारी हुई। 30 हजार जुड़े। 400 लोगों को सीधे तौर पर नौकरी मिली है।

बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने की दिशा में बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 साल में बड़े बदलाव दिखेंगे। मिलों के खुलने से बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। किसानों को प्रोत्साहन व गन्ने की खेती बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। **अनिल कुमार झा,** ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग

3 विशेषज्ञों को जिम्मेदारी

1. **डॉ. बक्शी राम** - सेवानिवृत वैज्ञानिक, सुगरकेन ब्रिडिंग इंस्टीट्यूट, कोयंबटूर।
2. **अमित कुमार सिंह** - प्रबंध निदेशक, वर्द्धन सीबीजी।
3. **मांडव प्रभाकर राव** - पूर्व अध्यक्ष, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन।

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट राजेंद्रनगर फिजिकल कॉलेज की खाली जमीन पर हो रहा निर्माण

पटना में बन रहा पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड अगले माह तैयार होगा

आलोक सिंह | पटना

राजेंद्रनगर फिजिकल कॉलेज की खाली जमीन पर निर्माणाधीन पटना का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी ग्राउंड फरवरी में तैयार हो जाएगा। इससे खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास शुरू हो सकेगा। लेकिन, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए फिलहाल सीधी सड़क नहीं है। एनसीसी मुख्यालय के रास्ते ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़क से ग्राउंड तक पहुंचा जा सकता है। दर्शक दीर्घा, वार्म अप ग्राउंड, चेंजिंग रूम और अन्य सुविधाओं के निर्माण में अभी लंबा समय लगेगा। इस कारण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन में एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। ग्राउंड का अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड के अच्छी तरह सूखने के बाद बिटविन के बाद डामर कोटिंग होगी। फिर साफ्ट पिट और तब जर्मनी से मंगाई जा रही पॉलीटेन ब्लू टर्फ लगाई जाएगी। पॉलीटेन ब्लू टर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर की सबसे लेटेस्ट टर्फ है। राजगीर और ओडिशा में भी यही टर्फ लगी है। यहां दिल्ली की सिन्कॉट इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है। बुडको के एमडी अनिमेश पराशर ने कहा-पटना के राजेंद्रनगर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम फरवरी तक बन कर तैयार हो जाएगा।

कभी दो मीटर पानी में डूबा रहता था मैदान

अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि यह दलदली जमीन को विश्वस्तरीय खेल मंच में बदलने की ऐतिहासिक कहानी भी है। जिस जगह इंटरनेशनल टर्फ बिछाने की तैयारी है, वहां कभी लगभग 2 मीटर तक पानी में डूबा दलदली क्षेत्र हुआ करता था। चारों ओर से लगातार पानी रिसाव, 3 मीटर तक ऊंची घास और दलदल की कई परतों के कारण यह मैदान वर्षों तक किसी भी खेल गतिविधि के योग्य नहीं था। मैदान को खेलने योग्य बनाने के लिए पटना मेट्रो से हजारों ट्रॉली विशेष मिट्टी मंगाई गई। मिट्टी गीली होने के कारण मैदान को सुखाने में ही एक महीने से अधिक का समय लग गया। दलदली पॉकेट्स को हटाने के लिए मशीनों से खुदाई कर रबल भरकर मैदान को स्थिर किया गया, जो इस परियोजना का सबसे कठिन हिस्सा रहा। जुलाई से अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश के कारण काम पूरी तरह ठप रहा।

भास्कर एक्सपर्ट योगेश कुमार (पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी, हॉकी कोच और कमेंटेटर)

खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास की सुविधा और राज्य को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा

राजगीर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से बिहार हॉकी को नई पहचान मिली है। लेकिन, राजगीर की दूरी पटना के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए बड़ी बाधा बनी रही। अब पटना में इंटरनेशनल टर्फ बनने से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास की सुविधा मिलेगी और राज्य को इसका दीर्घकालीन लाभ मिलेगा।

बिहार में उच्चतम भूकंपीय ज़ोन में दरभंगा और मधुबनी जिले शामिल

जासं, मुजफ्फरपुर : भूकंपीय जोनेशन में संशोधन किया गया है। इसमें अब नया जोखिम जोन-6 जोड़ा गया है। बिहार के दो जिलों दरभंगा व मधुबनी को उच्चतम भूकंपीय ज़ोन-6 में शामिल किया गया है। इसी तरह उच्च जोखिम वाले जोन में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर सहित कुल 12 जिले शामिल किए गए हैं। नई भूकंपीय जोन मैप में पूर्वी बिहार जैसे कोसी-सीमांचल क्षेत्र के जिले अधिक खतरे वाले क्षेत्र में आ गए हैं। पहले ये ज्यादातर जोन-4 में थे। अब इन्हें जोन-5 या जोन-6 में रखा गया है। इससे अब भवन निर्माण में भूकंपरोधी उपायों को कठोरता से अपनाना अनिवार्य होगा।

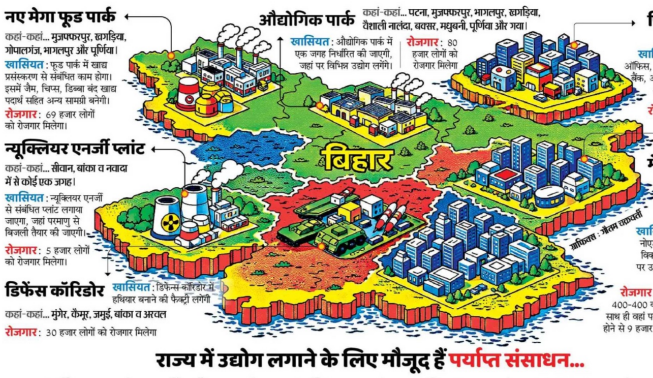

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से संशोधित भूकंपीय जोनेशन मानचित्र जारी किया गया है। भूकंप की विभीषिका को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 29 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा पखवारा मनाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत पूरे राज्य में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के अधीन भूकंप से बचाव की तैयारी व जागरूकता के कार्यक्रम किए जाने हैं।

नए बिहार की नींव...

ऐसा इसलिए.. क्योंकि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी-रोजगार देने की तैयारी

24 सौ साल पहले बिहार से चाणक्य ने दुनिया को बेहतरी का 'अर्थशास्त्र' दिया। आदर्श 'राज' की 'नीति' समझाई। आज उसी बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल करने का टास्क तय हुआ है। नई सरकार ने '7 निश्चय-3' को अपना रोडमैप बनाया है। सरकार का दावा है कि यह एक नई औद्योगिक क्रांति की नींव रखेगा। इसके लिए राज्य में अगले पांच वर्षों में 5 नए फूड पार्क, 10 औद्योगिक पार्क, एक फिनटेक सिटी, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, डिफेंस कॉरिडोर और 5 मेगा टेक सिटी बनाने की योजना है। इससे बिहार को अगले पांच वर्षों में बड़ी और चौतरफा उछाल मिलेगी। बिहार टॉप 5 विकसित राज्यों जैसा बनेगा। 5 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 1 करोड़ लोगों को नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य है।

नए मेगा फूड पार्क
कहां-कहां... मुजफ्फरपुर, खगड़िया, गोपालगंज, भागलपुर और पूर्णिया।
खासियत : फूड पार्क में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित काम होगा। इसमें जैम, चिप्स, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ सहित अन्य सामग्री बनेगी।
रोजगार : 69 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

औद्योगिक पार्क
कहां-कहां... पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया, वैशाली नालंदा, बक्सर, मधुबनी, पूर्णिया और गया।
खासियत : औद्योगिक पार्क में एक जगह निर्धारित की जाएगी, जहां पर विभिन्न उद्योग लगेंगे।
रोजगार : 80 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

फिनटेक सिटी
कहां-फतुहा
खासियत : फिनटेक सिटी में ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा एक्सचेंज, अंतरराष्ट्रीय कंपनी लगेगी।
रोजगार : 9 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट
कहां-कहां... सीवान, बांका व नवादा में से कोई एक जगह।
खासियत : न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित प्लांट लगाया जाएगा, जहां परमाणु से बिजली तैयार की जाएगी।
रोजगार : 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

मेगा टेक सिटी
कहां-कहां... पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, नालंदा।
खासियत : मेगा टेक सिटी में नोएडा, चंडीगढ़ की तरह शहर विकसित होंगे। इससे कुछ दूरी पर उद्योग लगेंगे; कारखाने होंगे।
रोजगार : प्रत्येक मेगा सिटी में ही 400-400 कर्मचारी काम करेंगे। इसके साथ ही वहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 9 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

डिफेंस कॉरिडोर
खासियत : डिफेंस कॉरिडोर में हथियार बनाने की फैक्ट्री लगेगी
कहां-कहां... मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका व अरवल
रोजगार : 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

राज्य में उद्योग लगाने के लिए मौजूद हैं पर्याप्त संसाधन...

पानी... 1 राज्य में 2251 किमी क्षेत्र में आठ नदियों का प्रवाह है। इसमें 445 किमी गंगा, 394 किमी बागमती प्रवाहित हो रही है। यहां उद्योग के लिए पर्याप्त पानी मौजूद है।

बिजली... 2 भविष्य के लिए चौसा और पीरपैती में थर्मल पावर प्लांट लग रहा है। लखीसराय के कजरा सोलर पावर प्लांट में बैट्री स्टोरेज क्षमता विकसित की जा रही है।

जमीन... 3 राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त जमीन है। बख्तियारपुर समेत अन्य जगहों पर औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ है।

परिवहन... 4 राज्य में एनएच की लंबाई 6131.8 किमी, एसएच की लंबाई 3713.97 किमी, रेल रूट की लंबाई 3888 किमी के साथ डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर भी है।

कच्चा माल... 5 एग्रो बेस्ड इंडस्टीज के लिए गेहूं, चावल, मकई, दाल, आलू सहित अन्य मोटे आनाज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

लेबर... 6 राज्य में स्किल्ड व अनस्किल्ड लेबर की उपलब्धता है। इसमें आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि में युवाओं की अधिक संख्या है।

नो निगेटिव मंडे 11 साल

अंदर पढ़िए

आज के अंक में नकारात्मकता सबसे पीछे

आज पूरा अखबार सकारात्मक... वो निगेटिव खबरें जो जानना बेहद जरूरी सबसे पीछे।

एक्सपर्ट से जानिए... कितनी है गुंजाइश, क्या हैं सिस्टम की कमजोरियां, क्यों रुक रहा निवेश

संसाधन हैं, नीति भी मौजूद... क्रियान्वयन बड़ी चुनौती

भास्कर एक्सपर्ट

रामलाल खेतान, अध्यक्ष, बीआईए | अभिषेक सिंह, अध्यक्ष, बिहार एंटरप्रेन्योर एसो. | विवेक शाह, अध्यक्ष, एसोचैम बिहार

बिहार में उद्योगों के विकास को लेकर माहौल बन चुका है। सड़क, बिजली, जमीन, मैन पावर और घोषित औद्योगिक नीतियां- सब कुछ मौजूद हैं। कृषि, कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, एथेनॉल, डेयरी और फार्मा जैसे सेक्टर संभावनाओं से भरे हैं। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर निवेश और रोजगार की रफ्तार उम्मीद से कम है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली चुनौती संसाधनों की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति, भरोसे और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की है। हालांकि धीरे-धीरे कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी का नतीजा है कि औद्योगिक इकाइयों से लेकर एमएसएमई इकाइयों तक में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अगले पांच साल सरकार उद्योग और रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस करनेवाली है। ऐसे में विश्वास है कि बिहार नए मुकाम पर खड़ा होगा।

आंकड़े भरोसा देते हैं...

औद्योगिक क्षेत्र... 2005 में 46 क्षेत्र थे, अब 94

औद्योगिक इकाइयां 1674 से बढ़कर ₹10,000

एमएसएमई इकाइयां 72000 से बढ़कर 350000

मेगा टेक सिटी	एमएसएमई पार्क	सेक्टर स्पेशल पार्क
05 बनेंगी	100 बनेंगे	10 बनेंगे

निर्यात... 25 करोड़ से 17,000 करोड़ रु.

• हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं-चनपटिया मॉडल के खराब हालात, इथेनॉल सेक्टर की अड़चनें जैसी कई बातें। नए टास्क के क्रियान्वयन की परीक्षा बाकी है।

जहां हम पिछड़े / जहां हम मजबूत

राज्य में औद्योगिक नीतियां हैं, पर जमीन पर असर कमजोर है। सिस्टम की खामियां निवेश रोकती हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर, श्रम बल और नई नीतियां उम्मीद जगाती हैं। सवाल है- रफ्तार कब आएगी?

जहां हम पिछड़े	जहां हम मजबूत
1. नीतियां हैं, लेकिन 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं। यही सबसे बड़ी कमजोरी।	1. उद्योग के लिए माहौल बना। नई-नई पॉलिसियां घोषित हो रही हैं।
2. सिंगल विंडो सिस्टम नाम का। भीतर कई खिड़कियां। उद्योगों को दिक्कत।	2. स्किल्ड व नन-स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध। श्रम लागत अपेक्षाकृत कम।
3. उद्योग लगाने पर लोकल बॉडी का हस्तक्षेप और सुरक्षा चिंता।	3. सड़क, बिजली, जमीन, लोकेशन- चारों प्रमुख आधार मौजूद।
4. ब्यूरोक्रेसी में व्यवहारिकता व जवाबदेही की कमी, व्यापारियों के प्रति निगेटिव अप्रोच।	4. कृषि प्रधान राज्य होने से फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य, बागवानी के लिए कच्चा माल प्रचुर।
5. स्किल्ड मैनपावर का पलायन। लौटने के लिए भरोसे का माहौल नहीं।	5. एथेनॉल, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, डेयरी जैसे सेक्टर तेजी से उभर रहे।
6. रिसोर्स मैपिंग व रिसर्च डेटा का अभाव। कौन सा उद्योग क्यों बंद हुआ, स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं।	6. 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का राज्य सरकार का फैसला।
7. दाल उत्पादन भरपूर, लेकिन दाल मिलों की भारी कमी। कच्चा माल बाहर जा रहा।	7. बंद पड़ी चीनी मिलों के रिवाइवल से रोजगार, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
8. बैंकिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल-फ्रेंडली नहीं। MSME को फाइनेंस में परेशानी।	8. गारमेंट इंडस्ट्री कम पूंजी (4-5 लाख) में शुरू। बड़े पैमाने पर रोजगार देने में सक्षम।
9. फार्मास्युटिकल खपत बड़ी होने के बावजूद उद्योग नगण्य, न फार्मा पार्क न पर्याप्त लैब।	9. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 से निवेश बढ़ने की उम्मीद।
10. माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को नीति स्तर पर अपेक्षित प्राथमिकता नहीं।	10. राज्य में फोरलेन, एनएच और एक्सप्रेस-वे, भविष्य के औद्योगिक कॉरिडोर का आधार।

सिकंदरपुर औद्योगिक पार्क, बिहटा पटना।

चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध मोतीपुर अब फूड पार्क के लिए जाना जा रहा...

बेला से मोतीपुर-पारू तक बढ़ा उद्योग का दायरा, इथेनॉल-टेक्सटाइल से थमा पलायन

बेला औद्योगिक क्षेत्र से निकलकर मुजफ्फरपुर में उद्योगों का विस्तार अब मोतीपुर और पारू तक पहुंच चुका है। कभी चीनी मिल के लिए पहचाना जाने वाला मोतीपुर अब इथनॉल और मेगा फूड पार्क के कारण नई औद्योगिक पहचान बना रहा है। वहीं बेला में टेक्सटाइल और पारू में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिली है। पांच साल पहले मोतीपुर में मेगा फूड पार्क के लिए आवंटित जमीन पर अब 14 फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं। यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्नैक्स, नूडल और रेडी-टू-ईट उत्पाद तैयार कर रही हैं। यहीं बना पोल्ट्री फीड दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक बाजार बना चुका है।

900 एकड़ में फैले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र ने इथनॉल उत्पादन में भी उपलब्धि हासिल की है। करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश से तीन इथनॉल इकाइयां चालू हो चुकी हैं, जबकि दो पाइपलाइन में हैं। 1970 के दशक में जहां मोतीपुर चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध था, अब वही इलाका इथनॉल और फूड पार्क के लिए जाना जा रहा है। मोतीपुर से 35 किमी दूर पारू में 700 एकड़ जमीन को नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इधर, 450 एकड़ में फैला बेला औद्योगिक क्षेत्र पहले फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां टेक्सटाइल उद्योग बूम पर है।

आईडीपीएल की 70 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल क्लस्टर

तीन दशक से बंद आईडीपीएल की 70 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया गया है, जहां ट्रॉली बैग, बैग, टी-शर्ट, जींस, ट्राउजर और होजियरी कपड़ों का उत्पादन हो रहा है। आईपीएल इकाई में उत्पादित उर्वरक की मांग तमिलनाडु तक है। सरकारी इकाइयों के स्थान पर निजी कल-कारखानों ने औद्योगिक गति को तेज किया है। इथनॉल फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग के साथ लेदर और टेक्सटाइल उद्योग नए स्वरूप में उभर रहे हैं। टेक्सटाइल उद्योग के कारण कामगारों का पलायन थमा है। केवल टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों में करीब 5 हजार श्रमिक कार्यरत हैं। दूसरे जिलों के कामगार भी अब यहां रोजी-रोटी कमाने पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में औद्योगिक नक्शे पर एक और बड़ा नाम जुड़ सकता है। अंबुजा कंपनी यहां सीमेंट फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है।

अंबुजा सीमेंट और लेदर पार्क की तैयारी

- उद्योग विभाग ने 61.82 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को भेजा।
- एक हिस्से में लेदर पार्क, दूसरे में अंबुजा का सीमेंट प्लांट प्रस्तावित।
- **महवल में अधिगृहित जमीन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा।**

किसानों और युवाओं को फायदा

- इथनॉल फैक्ट्री से मक्का जैसी नकदी फसल को बढ़ावा
- **किसानों को सशक्त करने की संभावना**
- फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विस्तार की जरूरत
- **गन्ने की खेती वाले क्षेत्र में चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने की पहल जरूरी**

बिहटा औद्यौगिक पार्क में 68 इकाइयों को मिली जमीन

पटना जिले के 3 औद्योगिक पार्क से 28 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार

पटना जिला में तीन औद्योगिक पार्क हैं। इनमें बिहटा, पाटलिपुत्र और फतुहा शामिल हैं। इन तीनों औद्योगिक पार्कों से 28 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इस रोजगार को बढ़ाने के लिए बख्तियारपुर में 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। यहां करीब 15 हजार रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग विभाग के पटना जिला में कार्यरत अधिकारियों के मुताबिक सभी चार औद्योगिक पार्कों के व्यवस्थित होने के बाद 50 हजार लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा।

बिहटा औद्योगिक पार्क : बिहटा औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल 1118 एकड़ है। इसके अलावा आईआईटी और एनआईटी को जगह दी गई है। बियाडा के अधिकारियों के मुताबिक यहां 68 इकाइयों को भूमि या शेड आवंटित किए गए हैं। इनमें से 38 यूनिटों में परिचालन शुरू हो चुका है। शेष 29 यूनिटों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन इकाइयों के माध्यम से 1800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इसके साथ ही 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा।

पाटलिपुत्र और फतुहा में उद्योग से 15 हजार से अधिक को रोजगार

शहर के बीचों-बीच पाटलिपुत्र औद्योगिक पार्क 150 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इसमें पुराने के साथ नए उद्योग और बड़ी कंपनियों को कार्यालय खोलने की जगह मिली है। इसमें आईटी कंपनियां और सर्विसेज कंपनियों के आने से बड़ी संख्या में सीधे तौर पर लोगों को नौकरियां मिली है। वर्तमान समय में यहां करीब 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है। वहीं, फतुहा औद्योगिक पार्क 356 एकड़ में फैला है। यहां 150 फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है।

मौर्यकाल का जलमार्ग हो या मुगलकाल का 'सिल्क रूट', पटना से जुड़े ढेरों औद्योगिक-कारोबारी दृष्टांत हैं

भारत का नया टेक हब बनेगा बिहार

बिहार को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ग्लोबल वर्क प्लेस और पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित करने की बात है। यह सब मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। दरअसल, उद्यम यहां के खून में है। गुलाम भारत में अंग्रेजों द्वारा सात समंदर पार ले जाए गए यहां के लोगों ने तो कई-कई नए देश बना दिए। उद्यम -उद्योग-कारोबार, यहां की माटी में रहा है। इसकी भरपूर गुंजाइश है। धारणा है कि प्राचीन काल का पट्टन या पत्तन, अभी का पटना है। पत्तन यानी पोत-बंदरगाह। मौर्यकाल का जलमार्ग हो या मुगलकाल का 'सिल्क रूट', पटना या बिहार से जुड़े ढेरों औद्योगिक-कारोबारी दृष्टांत हैं।

1985-90 के बाद से 2000 तक, टाटा को छोड़ लगभग सभी बड़े उद्योग बंद होते चले गए। वजह थी—'राज' और उसकी 'नीति'। फ्रेट इक्वलाइजेशन नीति ने बिहार की आर्थिक कमर तोड़ दी। खनिज बिहार का, कारखाने दूसरे राज्यों में लगे। मुख्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहे। बिहार बंटा खेत-खलिहान बिहार में, कारखाने झारखंड में। स्पेशल पैकेज, राजनीतिक एजेंडा भर रहा। रहनुमा खामोश रहे। जब-जब सत्ता में बैठे लोगों ने बिहार की बेहतरी की ठानी, नतीजे आए। एचईसी, बरौनी रिफाइनरी, कांटी और बाढ़ थर्मल, राजगीर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मढ़ौरा-मधेपुरा रेल फैक्ट्री, बेला रेल व्हील प्लांट-ऐसे ढेरों उदाहरण हैं।

यहां गुंजाइश थी... तभी तो 1820 में चंपारण में पहली चीनी मिल खुली

कभी उद्योग का हब था...

यहां गुंजाइश थी, तभी तो 1820 में चंपारण में पहली चीनी मिल खुली। 1903-04 में मढ़ौरा में कानपुर शुगर वर्क्स शुरू हुआ। 1914 तक लोहट, रैयाम और लौरिया में चीनी मिलें लग चुकी थीं। 1920 तक सीवान और समस्तीपुर में भी मिलें स्थापित हो गईं। 1868 में स्थापित टाटा समूह ने 1907 में बिहार में कदम रखा। इसके बाद टिस्को, फिर टाटा एयरलाइंस (1932) और टेल्को (1945) आईं। 1922 में समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल शुरू हुई। 1929 में मढ़ौरा की मॉर्टन फैक्ट्री लगी। उद्योगों की सूची काफी लंबी रही है।

अब हालात बदले हैं...

पहले केंद्र और बिहार सरकारों में टकराव आम बात थी। अब केंद्र और राज्य, दोनों जगह एनडीए सरकार है। इसे 'डबल इंजन' सरकार कहा जा रहा है। सरकार ने औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी है। बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के पूरा होने का दावा है। उद्योगों के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। सिस्टम को निवेशकों के लिए 'सरकार आपके द्वार' मोड में डाला गया है। चीफ सेक्रेट्री प्रत्यय अमृत खुद निवेशकों से संवाद कर रहे हैं। वे एयरपोर्ट लाउंज में भी 'उद्योग वार्ता' कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति लाई गई है।

मेहसी का पर्ल बटन, सिगोड़ी का कपड़ा, लखीसराय का सिंदूर और भागलपुर का सिल्क हमारी पहचान

पारंपरिक उद्योग फिर से जिंदा हों, तो साकार होगा मेड-इन बिहार का सपना

एक करोड़ रोजगार का लक्ष्य नई फैक्ट्रियों और निवेश तक सीमित नहीं है। बिहार की असली ताकत उन पारंपरिक उद्योगों में छिपी है, जिन्होंने कभी लाखों परिवारों का पेट पाला और प्रदेश को पहचान दी। मेहसी का पर्ल बटन, सिगोड़ी का कपड़ा, लखीसराय का सिंदूर और भागलपुर का सिल्क आदि उद्योग आज हाशिए पर हैं, लेकिन अगर इन्हें क्लस्टर आधारित नीति, बाजार और तकनीक का साथ मिल जाए, तो यही 'मेड-इन बिहार' मॉडल बनकर बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हैं। मेहसी में एक समय 160 फैक्ट्रियां थीं। आज उद्योग लगभग खत्म है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन और कारीगरी अब भी मौजूद है। उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि पर्ल बटन को फैशन और एक्सपोर्ट से जोड़ दिया जाए, तो यह फिर हजारों युवाओं को काम दे सकता है। सिगोड़ी में समस्या उत्पादन की नहीं, सिस्टम की है। दो करोड़ से ज्यादा का कपड़ा तैयार है, लेकिन सरकारी भुगतान अटका है। उद्योग मंत्री के स्तर पर अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय खरीद नीति लागू हो जाए, तो यहां के 500 लूम फिर से 10 हजार तक पहुंच सकते हैं।

टैक्स में सुधार हो तो सिंदूर उद्योग से हजारों को मिलेगा रोजगार

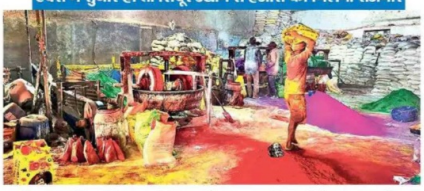

लखीसराय का सिंदूर उद्योग आज भी जिंदा है, लेकिन टैक्स असंतुलन ने इसे कमजोर किया। उद्योग विभाग के मुताबिक, अगर रंग-अबीर पर टैक्स में व्यावहारिक सुधार हो, तो यह सेक्टर फिर से प्रतिस्पर्धी बन सकता है और हजारों महिलाओं को रोजगार दे सकता है।

भागलपुर सिल्क को लेकर सरकार पहले ही ब्रांडिंग की बात कर चुकी है। चुनौती सस्ते आयात की है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट, डिजाइन इनोवेशन और टूरिज्म-हैंडलूम लिंक से यह उद्योग फिर से अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल कर सकता है।

क्लस्टर आधारित नीति बने, तो फिर से जिंदा होंगे कई उद्योग

क्लस्टर	पहले	मौजूदा स्थिति	री-स्टार्ट पर संभावना
मेहसी पर्ल बटन	160 फैक्ट्रियां, 10 हजार कारीगर	नामोनिशान मिटने के कगार पर	15-20 हजार रोजगार
सिगोड़ी कपड़ा	10 हजार लूम, 15 हजार रोजगार	500 लूम, 1000 लोग	10-15 हजार रोजगार
लखीसराय सिंदूर	20-25 टन/दिन उत्पादन	6 करोड़ का कारोबार	5 हजार+ रोजगार
भागलपुर सिल्क	600 करोड़ का कारोबार	2000 हैंडलूम	20-25 हजार रोजगार

क्यों खास हैं पारंपरिक उद्योग?

- कच्चा माल और हुनर स्थानीय
- पूंजी कम, रोजगार ज्यादा
- महिला व ग्रामीण भागीदारी अधिक
- पलायन रोकने में कारगर
- 'मेड-इन बिहार' की पहचान

समाधान का सीधा फॉर्मूला

- क्लस्टर आधारित नीति
- सरकारी खरीद में स्थानीय प्राथमिकता
- डिजाइन-टेक्नोलॉजी सपोर्ट
- ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट लिंक
- GI टैग/ब्रांडिंग

नीरा अब बिना केमिकल के छह महीने तक रह सकेगा ताजा

मनोज कुमार, पटना

खजूर और ताड़ से निकलने वाला पौष्टिक पेय नीरा अब छह माह तक ताजा रहेगा. बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) सबौर के वैज्ञानिकों ने इस पर दोबारा शोध शुरू किया है. बिना किसी केमिकल पदार्थ के मिलावट से नीरा को कमरे के तापमान पर छह महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा. इसकी पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है. नीरा संरक्षण की इस तकनीक का प्रदर्शन व प्रशिक्षण बिहार के 38 जिलों में किसानों, उद्यमियों और जीविका कैडर को दिया गया है. यह तकनीक किसानों और उद्यमियों के लिए आमदनी का नया रास्ता खोलेगी.

- वैज्ञानिकों ने शोध में परीक्षण कर निकाली नयी तरकीब, रिसर्च पेटेंट कराने की तैयारी शुरू

केमिकल युक्त नीरा 10 दिनों तक ही सुरक्षित रह सका : प्रयोग के तौर पर चूने की परत चढ़े मिट्टी के बर्तन को शाम में खजूर के पेड़ पर टांगा गया. सुबह सूर्योदय से पहले नीरा निकाला गया. संग्रहित नीरा को कोल्ड चेन के माध्यम से प्रयोगशाला लाया गया और विभिन्न प्रसंस्करण विधियों से गुजारते हुए अलग-अलग पैकेजिंग सामग्री में भरकर आगे की जांच की गयी. इसे कमरे के तापमान और शीत भंडारण दोनों स्थितियों में रखा गया. नियमित अवलोकन एवं रासायनिक विश्लेषण किये गये.

कोविड के कारण बंद हो गया था शोध, बीएयू ने दोबारा शुरू किया

वर्ष 2018-19 में नीरा संरक्षण को लेकर शोध शुरू हुआ था. वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण इस प्रयोग में बाधा आयी और इसे फिर आगे बंद कर दिया गया था. इस पर शोध करने के लिए उद्योग विभाग ने बीएयू को 25 लाख रुपये भी दिये थे. शोध कार्य बंद होने के बाद बीएयू ने लगभग 15 लाख रुपये उद्योग विभाग को लौटा दिये थे. इसके बाद दोबारा वर्ष 2023 में बीएयू ने इस पर दोबारा शोध किया. इस पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय ने 15 लाख रुपये दिये. 2023 में प्रयोगशाला स्तर पर कार्य पूर्ण हुआ और 2024 में औद्योगिक स्तर पर ले जाया गया. अब 2025 में इसे लॉन्च किया गया.

NATIONAL

Hindustan Page
Jansatta Page.

अंडमान में खुले समुद्र में मछली पालन परियोजना का शुभारंभ

श्री विजयपुरम, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देश की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइओटी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खुले समुद्र में सीबास और कोबिया मछलियों का पालन-पोषण किया जा रहा है, साथ ही प्रायोगिक तौर पर समुद्री शैवाल की खेती भी की जा रही है। सीबास और कोबिया दोनों ही उच्च मूल्य वाली मछलियां हैं जो अपने बेहतर स्वाद के लिए जानी जाती हैं। मंत्री ने इस परियोजना को भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में पहला बड़ा कदम बताया। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, एनआइओटी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

स्वदेशी हथियार, कितने तैयार

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वही देश बाहरी हमलों और रक्षा चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपट सकता है, जो हथियारों और रक्षा साजो-सामान के मामले में आत्मनिर्भर हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में राजग सरकार ने 2014 में सत्ता में आते ही बात को समझ लिया था और सरकार स्वदेशी रक्षा उद्योग का मजबूत ढांचा तैयार करने पर लगातार जोर दे रही है। आज सेना की गोला-बारूद की 90 प्रतिशत जरूरतें घरेलू रक्षा उद्योग पूरी कर रहा है। हाल में थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और स्वदेशी रक्षा आपूर्ति भविष्य के संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-इरान संघर्ष ने दिखाया है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में वही देश टिक सकते हैं, जिनका घरेलू उद्योग रक्षा आपूर्ति में सक्षम हो। आपरेशन सिंदूर के दौरान हमें घरेलू रक्षा उद्योग की क्षमताओं और कमियों का अंदाजा हो गया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा तभी सार्थक होगा, जब हमारी सेनाएं स्वदेशी ड्रोन से लेकर स्वदेशी लड़ाकू विमान तक से लैस हों। इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों और शोध एवं विकास के मजबूत ढांचे की जरूरत है। ऐसे समय में जब बांग्लादेश भी भारत के हितों के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की खतरनाक धुरी में शामिल होने की राह पर है, हमारी सुरक्षा चुनौतियां अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई हैं। ऐसे में स्वदेशी रक्षा उद्योग के वर्तमान इकोसिस्टम और शोध एवं विकास के लिए जरूरी संसाधनों के आवंटन की पड़ताल अहम मुद्दा है...

सेनाओं की 70 प्रतिशत तक जरूरतें पूरी कर रहा है घरेलू रक्षा उद्योग

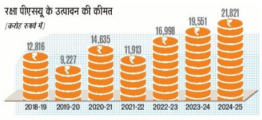

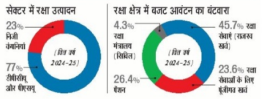

आपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देखी। विज्ञानियों के दशकों के प्रयास से देश ने यह क्षमता हासिल की है। आज देश का घरेलू रक्षा उद्योग सेनाओं की करीब 70 प्रतिशत जरूरतें पूरा कर रहा है। गोला-बारूद से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल टेक्नालाजी के मोर्चे पर देश तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। लड़ाकू विमान तेजस वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। अब इसके उन्नत संस्करण का उत्पादन भी तेज हो गया है और तेजस मार्क-2 की पहली उड़ान भी अगले कुछ वर्षों में प्रस्तावित है। देश स्वदेशी लड़ाकू विमानों और जेट इंजन का मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रयासरत है। **महेंद्र सिंह** बता रहे हैं घरेलू रक्षा उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के मोर्चे पर हम कहां खड़े हैं।

स्वदेशी होगा पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान

₹10,000 करोड़ पांचवीं पीढ़ी के विमान के विकास के लिए मंजूर किए हैं केंद्र सरकार ने

2035 तक बड़े पैमाने पर वायुसेना के लिए शुरू हो सकता है उत्पादन

- स्टेल्थ क्षमता से लैस पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है भारत, खत्म होगी आयात पर निर्भरता

डीआरडीओ बना रहा है भविष्य के हथियार

सिस्टम	टाइप	खासियत	वर्तमान स्थिति
हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल	रणनीतिक हमले के लिए	मैक 5 से अधिक गति	अंडर डेवलपमेंट
ब्रह्मोस एनजी	सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल	हवा से जमीन पर करती है हमला	चल रहे हैं परीक्षण
ब्रह्मोस-2	हाइपरसोनिक	1500 किलोमीटर रेंज	2026-27 में परीक्षण
अस्त्र एमके-2, एमके-3	एयर टू एयर	बियांड विजुअल	ट्रायल जारी
रुद्रम-2/4	एयर टू ग्राउंड	एंटी रेडिएशन	पाइपलाइन में

भारत को अभेद्य बनाएगा सुदर्शन चक्र

- हवाई हमलों को रोकने और जवाबी हमले के लिए विज्ञानी तैयार कर रहे सुदर्शन चक्र
- एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी प्रणालियों का नेटवर्क तैयार करेगा मल्टी लेयर एयर डिफेंस
- 2035 तक देश को हमलावर लड़ाकू विमान, मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ होगी सुदर्शन चक्र की तैनाती

चुनौतियां

- राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन न होना
- डीआरडीओ के प्रोजेक्ट को समय से मंजूरी न मिलना, फंड आवंटन में देरी
- सेनाओं और डीआरडीओ के बीच आपसी समन्वय और भरोसे की कमी

'मुकदमों के लिए आरटीआइ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वकील'

- केंद्रीय सूचना आयोग ने हरियाणा के एक मामले में दिया महत्वपूर्ण निर्णय

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने निर्णय दिया है कि वकील अपने मुवक्किलों के मुकदमों के लिए जानकारी जुटाने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह देखते हुए कि इस तरह से पारदर्शिता के कानून का उपयोग उसके मूल उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में विफल रहता है।

हरियाणा के जवाहर नवोदय विद्यालय में फलों और सब्जियों की आपूर्ति के अनुबंध की समाप्ति से संबंधित विवाद में एक वकील द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज करते हुए सूचना आयुक्त सुधा रानी रिलांगी ने संज्ञान लिया कि आवेदक ने 'अपने भाई की ओर से जानकारी मांगी, जो उत्तरदायी सार्वजनिक प्राधिकरण को सब्जियों/फलों का आपूर्तिकर्ता था।' आयोग ने कहा कि आपूर्तिकर्ता स्वयं जानकारी क्यों नहीं मांग सकता, इस संबंध में किसी स्पष्टीकरण के अभाव में 'ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने अपने मुवक्किल की ओर से जानकारी मांगी है, जो कि स्वीकार्य नहीं है।'

मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सीआइसी ने स्पष्ट किया कि 'एक प्रैक्टिसिंग वकील अपने क्लाइंट की ओर से दायर मामलों से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकता।' हाई कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अन्यथा, हर प्रैक्टिसिंग वकील अपने क्लाइंट की ओर से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआइ अधिनियम के प्रविधानों का उपयोग करेगा, जो इसके उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाता। आयोग ने इस निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि आरटीआइ अधिनियम के उद्देश्यों का निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता और इसे वकील के हाथों में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उपकरण नहीं बनना चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए कि कई रिकार्ड आग में नष्ट हो गए थे और व्यक्तिगत जानकारी को उचित रूप से छूट के तहत अस्वीकार किया गया था। सीआइसी ने कहा कि उसे 'सीपीआइओ द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया में कोई दोष नहीं मिला।'

PM launches ₹6,957-crore Kaziranga corridor work

Modi lays the foundation stone for the 86-km project, flags off two Amrit Bharat trains from poll-bound Assam; he accuses Congress of aiding infiltrators, neglecting Kaziranga National Park

काजीरंगा नेशनल पार्क भारत की जैव विविधता का एक अनमोल रत्न : पीएम

प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि असम का आत्मा और भारत की जैव विविधता का एक अनमोल रत्न है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान वन्यजीवों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब वे ऊंची जगहों की तलाश में नेशनल हाईवे पार करते हैं और अक्सर फंस जाते हैं। सरकार जंगल को सुरक्षित रखते हुए सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एलिवेटेड कारिडोर के पूरा होने के बाद वाहन ऊपर से गुजरेंगे, जबकि नीचे वन्यजीवों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। इसका डिजायन गैंडों, हाथियों और बाघों के पारंपरिक आवाजाही मार्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

मोदी ने जोर देकर कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से 2025 में काजीरंगा नेशनल पार्क में किसी भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। 2013 और 2014 में दर्जनों एक सींग वाले गैंडों को मार दिया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, वन विभाग को आधुनिक संसाधन प्रदान करने, निगरानी बढ़ाने और वन दुर्गा के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया।

• AGRICULTURE

India's record rice output comes with challenges

With output surging in recent years, India has crossed China to become the world's largest rice producer. Does it need to produce so much?

HARIKISHAN SHARMA

EARLIER THIS month, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan said India had surpassed China to become the world's largest rice producer in 2024-25.

India produced around 150 million metric tonnes while China produced 145.28 million tonnes in that year. India currently accounts for around 28% of global rice production. A decade ago, however, India's rice

• RICE PRODUCTION: THE RISE AND RISE

SOURCE: UPAG PORTAL OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE

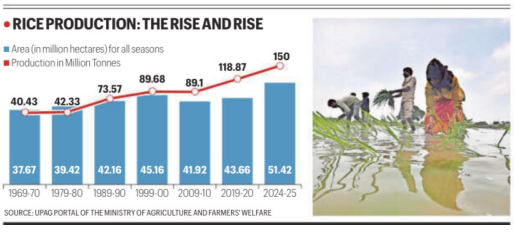

health and environmental challenges. It has also been grown in states already experiencing a decline in groundwater levels.

The rice yield also diverges widely across states due to factors such as agro-climatic conditions.

In 2024-25, the yield per hectare was 4,428 kg in Punjab, 3,928 kg in Andhra Pradesh, 2,561 kg in Bihar and 2,824 kg in Uttar Pradesh. The national average was 2,929 kg per hectare.

Moving away from paddy

With more and more farmers preferring paddy, the Union government has been focusing on crop diversification. It is not only looking at farm income and nutritional se-

Dainik Jagaran Page
Jansatta Page

INTERNATIONAL

आक्रोश • ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा प्रदर्शन, ट्रम्प के कब्जे के प्लान से गुस्सा बढ़ा

ट्रम्प के खिलाफ ग्रीनलैंड के लोग सड़कों पर आए; कहा- हमारा देश बिकाऊ नहीं

भास्कर न्यूज | वॉशिंगटन/नूक

ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले बयानों के खिलाफ शनिवार को राजधानी नूक में देश का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। पुलिस के मुताबिक इसमें नूक की करीब 10 हजार लोग आए थे, जो शहर की करीब आधी आबादी है। सड़कों पर हजारों लोग अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च करते हुए पहुंचे।

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय झंडे लहराए और ट्रम्प का पुतला लेकर 'ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है', 'अमेरिका वापस जाओ' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में परिवार भी बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता पर कोई सौदा मंजूर नहीं। अमेरिका के नए टैरिफ ऐलान ने माहौल और गरमा दिया।

राजधानी नूक में प्रदर्शन।

हम भी काउंटर टैरिफ लगाएंगेः यूरोप

ग्रीनलैंड मुद्दे पर ट्रम्प ने यूरोप के 8 देशों पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर अमेरिका दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगाएगा, तो ईयू भी जवाबी काउंटर-टैरिफ लगाएगा। यूरोप का कहना है कि वह अपने हितों और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। हालांकि ईयू ने अभी जवाबी टैरिफ का प्रतिशत तय नहीं बताया है।

विरोधः मेलोनी बोलीं- ब्लैकमेल नहीं चलेगा; मैक्रों ने कहा- धमकी से यूरोप नहीं झुकेगा

ईयू में ट्रम्प के ग्रीनलैंड बयान और टैरिफ दबाव से ईयू-यूएस ट्रेड एग्रीमेंट संकट में है। यूरोप के नेता इस कदम को दबाव की राजनीति बता रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संकेत दिए कि यूरोप 'ब्लैकमेल' के आगे नहीं झुकेगा। वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि कोई भी धमकी यूरोप का रास्ता नहीं बदल सकती।

ट्रम्प के खास नवारो बोले- भारत में एआई का खर्च अमेरिकी क्यों उठाएं, कदम उठेगा

ट्रम्प के पूर्व व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि अमेरिकी यूजर्स भारत में एआई सेवाओं के लिए भुगतान क्यों करें? जबकि ये प्लेटफॉर्म अमेरिका में बनते हैं और अमेरिकी जमीन व बिजली पर चलते हैं। नवारो ने इसे 'ट्रेड इश्यू' बताते हुए कहा कि इस समस्या से निपटना होगा और जरूरत पड़ी तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है।

वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने को भारत तैयार

दावोस, प्रेट्र : दावोस में सोमवार से शुरू हो रहे पांच दिवसीय विश्व आर्थिक मंच के 56वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसमें सरकार, व्यापार जगत, शिक्षा जगत, बहुपक्षीय संगठनों, नागरिक समाज और श्रमिक संघों से जुड़े 130 से अधिक देशों के लगभग तीन हजार वैश्विक नेता शिरकत कर रहे हैं। इनमें 1,700 से अधिक उद्यमी शामिल हैं जिनमें से आधे कंपनी या व्यापारिक समूहों के सीईओ या अध्यक्ष हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्दों के अलावा यूक्रेन, गाजा और वेनेजुएला सहित लैटिन अमेरिका के मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

ट्रंप अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आ रहे हैं। इनमें विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वित्त मंत्री स्काट बेसेंट, वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक, ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर के शामिल होने की उम्मीद है। दुनिया भर से कम से कम 64 राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे, जबकि जी-7 देशों में से छह देशों के शीर्ष नेतृत्व का भी प्रतिनिधित्व होगा। चीन और पाकिस्तान के बड़े प्रतिनिधिमंडल भी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। विश्वभर से रिकार्ड संख्या में 400 शीर्ष राजनीतिक नेता इस बैठक में शामिल होंगे। 30 से अधिक विदेश मंत्री, 60 से अधिक वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर तथा 30 से अधिक व्यापार मंत्री भी इसमें शामिल होंगे।

भारत से चार केंद्रीय मंत्री - अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रल्हाद जोशी और के. राममोहन नायडू - और छह मुख्यमंत्री, साथ ही देश के 100 से अधिक शीर्ष सीईओ के उपस्थित रहने की उम्मीद है। मुख्यमंत्रियों में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, असम के हिमंता बिस्वा सरमा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, तेलंगाना के ए. रेवंत रेड्डी और झारखंड के हेमंत सोरेन हैं। भारतीय नेता कई चर्चाओं में भाग लेंगे। इनमें 'क्या भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है' विषय पर एक चर्चा भी शामिल है। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख कारोबारी नेताओं में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी, टाटा समूह के एन. चंद्रशेखरन, बजाज समूह के संजीव बजाज, जुबिलेंट भारती समूह के हरि एस. भारती, टीवीएस मोटर्स के सुदर्शन वेणु और महिंद्रा समूह के अनीश शाह शामिल हैं।

अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था : सशस्त्र बलों के पांच हजार से अधिक जवान, महत्वपूर्ण स्थानों पर स्नाइपर, एआइ-संचालित ड्रोन और जासूसी उपकरणों तथा खुफिया गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विशेष उपकरण तैनात किए गए हैं।

▶ दावोस में आयोजित हो रहे विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं कई देश

▶ पांच दिनों के इस सम्मेलन में तीन हजार से अधिक वैश्विक नेताओं में डोनाल्ड ट्रंप भी हैं शामिल

दावोस में विश्व आर्थिक मंच के आयोजन स्थल पर रविवार को कार्य में जुटे लोग। एपी

दावोस : कभी स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र रहा, अब ऐतिहासिक चर्च में बना 'यूएसए हाउस'

एक वक्त था जब दावोस स्वास्थ्य पर्यटन का प्रमुख केंद्र होता था। वर्ष 1880 में टीबी की बीमारी से पीड़ित अंग्रेज स्वस्थ होने की उम्मीद में दावोस की आबोहवा में शरण लेने आए। उन्होंने यहां चर्च भी बनवाया। वही ऐतिहासिक चर्च अब विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, व्यापारियों व अन्य लोगों के लिए 'यूएसए हाउस' के रूप में मेजबानी करेगा। इस छोटे से शहर के मुख्य सैरगाह पर स्थित किर्चे चर्च को 1970 के दशक के उत्तरार्ध में काम्प्लेक्स बनाने के लिए ध्वस्त किया जाना था, पर लोगों ने एकजुट होकर इसे रोक दिया। अब, चर्च को स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और स्विट्जरलैंड के फ्री इवेंजेलिकल चर्च के गेमाइंडेबुंड ने इसका स्वामित्व ले लिया है।

भारत में एआइ के लिए अमेरिका के लोग क्यों कर रहे भुगतान : नवारो

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जनवरी।

वाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि अमेरिका के नागरिक भारत में कृत्रिम मेधा (एआइ) के लिए भुगतान क्यों कर रहे हैं?

नवारो की ये टिप्पणियां भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच शनिवार को आईं। नई दिल्ली-वाशिंगटन के संबंधों में खटास की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसद शुल्क (टैरिफ) लगाने के बाद हुई। इस शुल्क में रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 फीसद का अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।

नवारो ने 'रियल अमेरिकाज वायस' के साथ साक्षात्कार में कहा, 'सवाल यह उठता है कि अमेरिका के नागरिक भारत में एआइ के लिए भुगतान क्यों कर रहे हैं? चैट जीपीटी अमेरिकी जमीन पर काम कर रहा है, अमेरिकी बिजली का उपयोग कर रहा है और चैट जीपीटी के बड़े उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है, उदाहरण के लिए भारत, चीन और दुनिया के अन्य हिस्सों में। इसलिए यह एक और मुद्दा है, जिसे सुलझाया जाना चाहिए।'

यूएई के राष्ट्रपति नाहयान आज आएंगे भारत, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी यानी सोमवार को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। उनका भारत दौरा मध्य पूर्व में ईरान-अमेरिका संबंधों में भारी तनातनी, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूएई के बीच बढ़ता तनाव और गाजा में अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य के बीच हो रहा है।

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। फाइल

नाहयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा उद्योग सहयोग और ऊर्जा पहलों पर चर्चा होने की संभावना है। यह यूएई के नेता का भारत में शीर्ष पद संभालने के बाद तीसरा आधिकारिक दौरा होगा और पिछले 10 वर्षों में देश का पांचवां दौरा होगा। भारत और यूएई के बीच 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार और जनसंपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ट्रंप का आठ यूरोपीय देशों पर 10% शुल्क का एलान

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के रुख का विरोध कर रहे थे, कहा- नहीं माने तो जून से 25 फीसद शुल्क

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जनवरी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के आठ देशों पर 10 फीसद शुल्क लगाने का एलान किया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड शुल्क के दायरे में आएंगे। इन पर एक फरवरी से शुल्क लागू होगा। रविवार को कई यूरोपीय नेताओं और सांसदों ने यूरोपीय संघ से मांग की कि वह पहली बार अपने दबाव विरोधी तंत्र का इस्तेमाल करे और उसे सक्रिय करे।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है, तो एक जून से यह शुल्क बढ़ाकर 25 फीसद कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने पोस्ट में 'ग्रीनलैंड की पूर्ण और पूरी खरीद' के लिए सौदे की बात कही है और साफ किया है कि तय समय तक समझौता नहीं होने पर शुल्क बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि हमने कई वर्षों तक डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन के सभी देशों और कुछ और देशों को सब्सिडी दी है। हमने उनसे शुल्क या किसी भी तरह का कोई कर नहीं लिया। अब सदियों बाद समय आ गया है कि डेनमार्क बदले में कुछ लौटाए क्योंकि अब विश्व शांति दांव पर है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं और डेनमार्क इसे चाहे भी तो नहीं रोक सकता। ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका पिछले 150 वर्षों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा है और कई राष्ट्रपतियों ने इसके प्रयास किए, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इनकार किया।

शनिवार को ट्रंप के इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। इस बीच फिलहाल यूरोपीय संघ के अध्यक्ष देश साइप्रस ने ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ के मुख्यालय में, यूरोपीय संघ के राजदूतों की आपात बैठक बुलाई है।

फ्रांस की ओर से संकेत मिला है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूरोपीय प्रतिक्रिया को एकजुट करने और दबाव विरोधी तंत्र लागू किए जाने पर सहमति जुटाने की कोशिश में हैं। हाल के दिनों में कई यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सेना भेजी है, उनका कहना है कि वे वहां आर्कटिक सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए हैं। ट्रंप की घोषणा शनिवार को तब हुई जब हजारों ग्रीनलैंडवासी राजधानी नूक में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर रहे थे।

रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वे डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों के साथ ग्रीनलैंड की स्थिति पर बातचीत करने के लिए शुल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण मानते हैं। डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड को इस शुल्क का सामना करना पड़ेगा। एक यूरोपीय राजनयिक के अनुसार, यह सवाल तुरंत उठ रहा है कि वाइट हाउस इस शुल्क को कैसे लागू करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि व्यापार के मामले में यूरोपीय संघ एक एकल आर्थिक क्षेत्र है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप अमेरिकी कानून के तहत कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, हालांकि वे आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का हवाला दे सकते हैं, जिन पर वर्तमान में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के बीच विभाजन से चीन और रूस को फायदा होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा खतरे में है, तो हम नाटो के भीतर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं।

नाराज यूरोपीय नेताओं एवं राजनयिकों ने चेतावनी दी

ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर 10 फीसद शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से नाराज यूरोपीय नेताओं एवं राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि यह कदम अमेरिका-यूरोप संबंधों को कमजोर कर सकता है और एक 'खतरनाक नकारात्मक दौर' को जन्म दे सकता है। अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड की ओर से रविवार को जारी एक असामान्य और बेहद सशक्त संयुक्त बयान में कहा गया कि डेनिश सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 'आर्कटिक एंड्योरेंस' के लिए ग्रीनलैंड भेजे गए सैनिक 'किसी के लिए कोई खतरा नहीं हैं।'

कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी जता चुके हैं विरोध

कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। नाटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड के तरफ हमारी जिम्मेदारी बरकरार है। ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों का फैसला है। कार्नी ने नाटो सहयोगियों, खासकर अमेरिका से कहा कि वे अपने वादों का सम्मान करें।

ग्रीनलैंड को लेकर शुल्क लगाने की ट्रंप की धमकी बिल्कुल गलत : स्टार्मर

लंदन, 18 जनवरी (भाषा)।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की कोशिश का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी को पूरी तरह से गलत करार दिया है। स्टार्मर ने इस प्रस्तावित कदम का विरोध कर रहे अन्य यूरोपीय सहयोगियों का शनिवार रात को समर्थन किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ' पर इस योजना के बारे में पोस्ट किया था।

किअर स्टार्मर

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 10 फीसद शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्होंने यह भी धमकी दी कि यदि आर्कटिक में स्थित स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड पर समझौता नहीं हुआ तो यह शुल्क और भी बढ़कर 25 फीसद तक पहुंच सकता है। स्टार्मर ने कहा, 'ग्रीनलैंड पर हमारा रुख बहुत स्पष्ट है - यह डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है और इसका भविष्य ग्रीनलैंडवासियों और डेनमार्क के लोगों का मामला है।' उन्होंने कहा, 'हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आर्कटिक सुरक्षा नाटो के लिए महत्वपूर्ण है और सभी सहयोगियों को आर्कटिक के विभिन्न हिस्सों में रूस से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिए।' प्रधानमंत्री ने कहा,'नाटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर शुल्क लगाना पूरी तरह गलत है। हम निश्चित रूप से इस मामले को सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएंगे।'

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप की धमकी को 'अस्वीकार्य' बताया। दूसरी ओर ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों लोग अमेरिका की कब्जे की धमकियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि यूरोपीय सहयोगी 'ब्लैकमेल' नहीं होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला डेर लेयेन ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता अंतरराष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांत हैं। उन्होंने चेतावनी दी, 'शुल्क लगाने से अटलांटिक-पार संबंध कमजोर होंगे।'

गाजा शांति निकाय के लिए ट्रंप का मोदी को न्योता

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जनवरी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'बोर्ड आफ पीस' का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। यह निकाय, गाजा में स्थायी शांति लाने और 'वैश्विक संघर्ष' के समाधान के लिए 'एक साहसिक नए दृष्टिकोण' पर काम करेगा। ट्रंप ने मोदी को एक पत्र लिखा, जिसे भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर साझा किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मध्य पूर्व में 'शांति बहाल करने के बाकी पेज 8 पर

सिंगूर में मोदी ने कहा, तृणमूल का 'महाजंगल राज' खत्म करना जरूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर 'वोट बैंक' की राजनीति के लिए घुसपैठियों की मदद करके राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के 'महाजंगल राज' को समाप्त करना राज्य में कानून व्यवस्था, विकास और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आगामी चुनाव के मद्देनजर मुकाबले को मोदी ने रविवार को सिंगूर में जनसभा में महाजंगल राज और सुशासन' के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किया।

-पूरी खबर पेज 2

सिंगूर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

EDITORIAL

Jansatta Page
Dainik Jagaran Page

टकराव की ओर अमेरिका-यूरोप

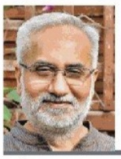

शिवकांत शर्मा

ग्रीनलैंड को लेकर नाटो और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया नाराजगी भरी तो है, लेकिन यह पता नहीं कि ट्रंप से टक्कर लेने के मामले में वे कितने पानी में हैं

वेनेजुएला पर हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो को पत्नी समेत अगवा करा लेने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने डेनमार्क के स्वायत्त द्वीप ग्रीनलैंड को छीनने की मुहिम तेज कर रखी है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो कनाडा और यूरोप के बीच उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैला है। उत्तरी ध्रुव से सटा होने के कारण तटवर्ती पट्टियों को छोड़कर इसका 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग बर्फ की एक से तीन किमी मोटी परत से ढका रहता है। दक्षिणी ध्रुव के बाद सबसे अधिक बर्फ ग्रीनलैंड की इस परत में ही जमा है जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल कर किनारों की तरफ खिसक रही है।

ग्रीनलैंड के साथ-साथ उत्तरी ध्रुव सागर की बर्फ भी तेजी से पिघल रही है जिसकी वजह से समुद्री यातायात के नए जलमार्ग खुल रहे हैं जो रूस, चीन और जापान से उत्तरी अमेरिका और यूरोप की दूरी को बहुत कम कर देते हैं। उत्तरी ध्रुव सागर से ग्रीनलैंड सागर होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में खुलने वाले इन मार्गों का प्रयोग करने के लिए रूस और चीन अपने विशेष युद्धपोतों और पनडुब्बियों का विकास कर रहे हैं ताकि वहां अपना वर्चस्व कायम कर सकें। इस जलमार्ग पर स्थित होने के कारण ग्रीनलैंड का भूराजनीतिक और सामरिक महत्व हमेशा से रहा है। दूसरे महायुद्ध में उसने हिटलर के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे 10 करोड़ डालर के सोने से खरीदने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। उसके बाद 1951 में डेनमार्क ने अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा में विशेष भूमिका देते हुए सैनिक अड्डे बनाने का अधिकार दे दिया था। इसके अलावा ग्रीनलैंड में तेल, गैस और उन दुर्लभ खनिजों के भंडार भी हैं जो इलेक्ट्रानिक और रक्षा उपकरणों और स्वच्छ ऊर्जा की बैटरियों के लिए आवश्यक होते हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी अटलांटिक महासागर में रूस और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व होना आवश्यक है। इसके बिना न ग्रीनलैंड अपनी रक्षा कर पाएगा और न वे उसकी रक्षा कर सकेंगे। इसलिए सीधे या टेढ़े रास्ते से वे उसे लेकर रहेंगे। उन्होंने भी ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने कहा उनका देश बिकाऊ नहीं है। डेनमार्क अमेरिका का दो सौ साल पुराना दोस्त है और स्थापना के समय से ही नाटो का सदस्य रहा है। उसने कोई 300 वर्ष पहले

अमेरिका-यूरोप के संबंधों को बिगाड़ता ट्रंप का अड़ियल रवैया। फाइल

ग्रीनलैंड को अपना उपनिवेश बनाया था, परंतु 1979 के बाद से ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वायत्त है। केवल विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क संभालता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। उसके सभी 56 हजार इन्युइट आदिवासियों को डेनिश नागरिकता प्राप्त है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नील्सन का कहना है कि यदि उन्हें अमेरिका और डेनमार्क में से एक को चुनना पड़ा तो वे डेनमार्क में रहना पसंद करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर या कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था किसी भी महाशक्ति को किसी दूसरे देश की संप्रभुता जबरन छीनने का अधिकार नहीं देती, लेकिन हाल के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून की जरूरत नहीं है।' सवाल यह है कि यदि ट्रंप सहयोग करने और सुविधाएं देने के लिए तैयार एक संप्रभु मित्र देश को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जबरन हथियाना आवश्यक और वैध मानते हैं तो उनमें और पुतिन में क्या फर्क है? बल्कि पुतिन तो उनकी तुलना में नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके शब्दों में, उनकी सैनिक कार्रवाई तो 'यूक्रेन से नात्सीवादी ताकतों का सफाया कर नाटो की बढ़त को रोकने के लिए है।' ट्रंप की दलील के आधार पर चीन का ताइवान पर कब्जा कर लेना तो और भी जायज माना जाएगा, क्योंकि शी चिनफिंग तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टूट कर अलग हुए देश और समाज के हिस्से को जोड़ने का कार्य करेंगे। दूसरे महायुद्ध के बाद एक नियमबद्ध व्यवस्था की स्थापना करके राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतंत्र और मुक्त व्यापार की हिमायत करते आ रहे देश के राष्ट्रपति का अंतरराष्ट्रीय कानून का इस तरह मखौल उड़ाना विश्व व्यवस्था के लिए गंभीर संकट का संकेत है। इस स्थिति के लिए काफी हद तक यूरोपीय संघ और अमेरिका से इतर नाटो के देश खुद जिम्मेदार हैं। ट्रंप और उनकी सरकार के आपत्तिजनक बयानों का एक सुर में कड़ा विरोध करने और ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए नाटो सेनाओं को तैनात करने के बजाय वे उसी तरह की जी हुजूरी में लगे हुए हैं, जैसी ट्रंप के मनमाने टैरिफों के एलान पर की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले की कड़ी निंदा से बचने के लिए भारत और चीन जैसी दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख शक्तियों की निंदा करने वाले यूरोपीय देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले पर जैसी बगलें झांकीं, उससे भी उनकी खासी फजीहत हो रही है।

अब जब ग्रीनलैंड और डेनमार्क की संप्रभुता को लेकर पानी सिर से ऊपर जा चुका है तब भी डेनमार्क के साथ केवल ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे चंद देशों ने ही अपनी टुकड़ियां ग्रीनलैंड भेजी हैं। इन मुट्ठी भर देशों की हिम्मत तोड़ना ट्रंप के लिए बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप के आठ देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है और उसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर नाटो और यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया नाराजगी भरी है, लेकिन यह पता नहीं कि ट्रंप से टक्कर लेने के मामले में वे कितने पानी में हैं। नाटो की एक समस्या यह है कि एक पर हमला सभी पर हमले का सिद्धांत नाटो के ही किसी सदस्य पर दूसरे सदस्य के हमले की स्थिति में स्पष्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर 1974 में साइप्रस द्वीप पर फैली हिंसा में जब नाटो सदस्य तुर्किये ने दूसरे नाटो सदस्य ग्रीस पर हमला बोल दिया था तब नाटो के समक्ष धर्मसंकट खड़ा हो गया था कि किसका पक्ष ले। अंत में अमेरिका ने बीच-बचाव कर सुलह कराई थी। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेने से और भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है, जिसके लिए नाटो अभी तैयार नजर नहीं आता।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

कल्याणकारी कदम

यूजीसी ने बनाई नीति, हर संस्थान में होगा मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, इन मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात होंगे पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ

अब छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी परखेंगे उच्च शिक्षण संस्थान

अरविंद पांडेय • जागरण

नई दिल्ली : उच्च शिक्षण संस्थान अब छात्रों की पढ़ाई के साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी परखेंगे। यदि किसी छात्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं दिखी तो तुरंत इसे संस्थान में स्थापित मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में भेंजेंगे, जहां पेशेवर (प्रोफेशनल) मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उसकी जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर उसे समुचित उपचार भी मुहैया कराएंगे। इसके लिए देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने परिसर में एक मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं व तेजी से सामने आ रहे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इससे निपटने के लिए एक एकीकृत नीति तैयार की है। इसे पिछले दिनों यूजीसी बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को अपने बुनियादी ढांचे में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के लिए भी एक जगह सृजित करने के लिए कहा है। साथ ही इनमें प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। वहीं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पांच सौ छात्रों पर एक वरिष्ठ शिक्षक को बतौर मेंटर एवं छात्रों के बीच से प्रत्येक सौ छात्रों पर एक सहायक छात्र की तैनाती करने को कहा है।

हेल्पलाइन नंबर भी होगा स्थापित : यूजीसी ने इसके साथ ही प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान से छात्रों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित करने को कहा है, जहां छात्रों को किसी भी समय मदद मिल सके। इस नीति में यूजीसी ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक संस्थान से एक कार्ययोजना भी बनाने को कहा है। ताकि किसी छात्र के अवसाद में दिखने पर या उससे ग्रसित होने की सूचना पर तुरंत प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। इसके लिए संस्थान के कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षित करने के भी सुझाव दिए हैं, ताकि खतरे को भांपते हुए तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकें। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ नीति को साझा करते हुए तुरंत इसके अमल एवं उससे जुड़े सुझाव देने को कहा है।

- प्रत्येक पांच सौ छात्रों पर एक फैकल्टी को भी बतौर मेंटर किया जाएगा नियुक्त

प्रतीकात्मक

इसलिए यह कदम उठाने की पड़ी जरूरत

- देश की कुल जनसंख्या में करीब 10.6 प्रतिशत लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से पीड़ित
- इनमें 18 से 29 वर्ष वर्ग के 7.3 प्रतिशत युवा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से घिरे
- एनसीआरबी की रिपोर्ट, देश में कुल आत्महत्याओं में करीब 7.6 प्रतिशत मामले छात्रों के

जम्मू-कश्मीर में 'क्रिप्टो हवाला' के इस्तेमाल का संदेह | **खुलासा** | उच्च सतर्कता बरत रहीं सुरक्षा एजंसियां

घाटी में अलगाववादी तत्त्वों को पुनर्जीवित करने की साजिश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 जनवरी।

सुरक्षा एजंसियों ने एक 'क्रिप्टो हवाला' नेटवर्क का पता लगाया है, जो देश के वित्तीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हुए जम्मू-कश्मीर में विदेशी धन का अवैध प्रवाह कर रहा है। इससे गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं कि इस धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस आशंका के बाद सुरक्षा एजंसियां उच्च सतर्कता बरत रही हैं।

उन्होंने चेताया कि इस गुप्त धन का उद्देश्य अलगाववादी तत्त्वों को पुनर्जीवित करना और केंद्र-शासित प्रदेश के भीतर राष्ट्र-विरोधी विमर्श को फिर से भड़काना है, जिसे पुलिस और केंद्रीय एजंसियों की कार्रवाई से लगभग निष्क्रिय कर दिया गया था। परंपरागत हवाला प्रणाली में जहां गैर-बैंकिंग तंत्र के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, वहीं 'क्रिप्टो हवाला' के तहत डिजिटल तरीके से अनियमित क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लेन-देन का पता लगाना संभव न हो।

भारत में जहां सभी 'वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर' (वीडीए एसपी) के लिए वित्तीय खुफिया इकाई के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है, वहीं यह क्रिप्टो हवाला नेटवर्क पूरी तरह से गुप्त रूप से संचालित होता है। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा एजंसियों के साथ किए गए एक विस्तृत अध्ययन में चीन, मलेशिया, म्यांमा और कंबोडिया जैसे देशों के लोगों की पहचान की गई है, जो केंद्र-शासित प्रदेश के लोगों को निजी 'क्रिप्टो वालेट' बनाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। ये वॉलेट अक्सर 'वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क' (वीपीएन) का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, ताकि इनके बारे में पता न चल सके और इनमें ग्राहक की पहचान के सत्यापन की आवश्यकता न हो।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घाटी में वीपीएन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि हाल में इस क्षेत्र में 'क्रिप्टो वालेट' में पंजीकरण के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। 'वीपीएन', आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए पहचान से बचने का एक साधन है। अधिकारियों ने बताया कि विदेश में बैठा आका सीधे इन निजी वालेट में क्रिप्टोकरंसी भेजता है, जिससे विनियमित वित्तीय संस्थान को शामिल किए बिना लेन-देन होता है, और वालेट धारक दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों की यात्रा करता है, ताकि अनियमित तरीके से नकदी के बदले क्रिप्टोकरंसी बेच सके।

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा केंद्रीय सुरक्षा एजंसियों के साथ किए गए एक विस्तृत अध्ययन में चीन, मलेशिया, म्यांमा और कंबोडिया जैसे देशों के लोगों की पहचान की गई है। जो केंद्र-शासित प्रदेश के लोगों को निजी 'क्रिप्टो वालेट' बनाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं।

बढ़ता प्रदूषण, घटता वित्त पोषण

दुनिया के तमाम देश और विकास एजंसियां स्वच्छ वायु को लेकर बड़े-बड़े वादे तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है, जो हवा को और जहरीला बना रही हैं। यह स्थिति नीतिगत विफलता का परिणाम है।

कुमार सिद्धार्थ

स्वच्छ हवा आज दुनिया की सबसे बुनियादी जरूरतों में शामिल है, लेकिन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था इसे अब भी प्राथमिकता नहीं मानती। 'क्लीन एअर फंड' की ताजा वैश्विक रपट ने एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को सामने रखा है कि दुनिया के तमाम देश और विकास एजंसियां स्वच्छ हवा के लिए बड़े-बड़े वादे तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका धन उन्हीं परियोजनाओं में जा रहा है, जो हवा को और जहरीला बना रही है। यह स्थिति केवल नीतिगत विफलता नहीं है, बल्कि एक ऐसे वैश्विक अन्याय का उदाहरण है, जिसका सबसे भारी बोझ भारत जैसे विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

क्लीन एअर फंड' की रपट के मुताबिक वर्ष 2023-24 के दौरान कई देशों की सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने जीवाश्म ईंधन को लंबे समय तक बनाए रखने वाली परियोजनाओं में वित्तीय राशि अस्सी फीसद बढ़ा कर 9.5 अरब डालर कर दी है। इसके उलट, स्वच्छ हवा और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए दी जाने वाली सहायता घट कर 3.7 अरब डालर रह गई, जो कुल वैश्विक विकास सहायता का महज एक फीसद ही है। यह आंकड़ा बताता है कि विकास वित्त और मानव स्वास्थ्य के बीच की खाई कितनी गहरी होती जा रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए वित्त पोषण घट रहा है। हर वर्ष होने वाले अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन चाहे वे जलवायु पर हों या स्वास्थ्य पर, ये स्वच्छ हवा को मानव अधिकार के रूप में स्वीकार करते हैं। मगर जब बजट आबंटन की बात आती है, तो वही सरकारें और संस्थाएं पीछे हट जाती हैं।

ऐसा लगता है कि वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्थाएं प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की वास्तविक कीमत को समझने के बजाय आर्थिक और कारोबारी हितों को अधिक महत्त्व दे रही हैं। इससे कई देशों के सामने जोखिम लगातार बढ़ रहा है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब दुनिया की सबसे बड़ी विकास एजंसी 'यूएसएड' के बंद होने और विश्व बैंक पर जीवाश्म ईंधन ऋण बढ़ाने के दबाव जैसी चर्चा सामने आती हैं। इन फैसलों ने स्वच्छ हवा के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों की रीढ़ कमजोर कर दी है। 'क्लीन एअर फंड' की मुख्य कार्यकारी जेन बर्स्टन की चेतावनी इस संदर्भ में बेहद अहम है अगर दिशा नहीं बदली गई, तो आने वाले वर्षों में करोड़ों और लोग जहरीली हवा के कारण जान गंवाएंगे।

गौरतलब है कि आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में हर साल लगभग 57 लाख लोगों की जान ले रहा है। यह संख्या वर्ष 2040 तक 62 लाख तक पहुंच सकती है। यह कोई संभावित खतरा नहीं, बल्कि चलती-फिरती महामारी है, जो चुपचाप समाज के सबसे कमजोर तबकों को निगल रही है। यह संकट सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है। यह बताता है कि वैश्विक राजनीति में किसकी जिंदगी की कीमत क्या है। लिहाजा अब इसे समझने और सचेत होने की जरूरत है। वैश्विक रपट यह भी दिखाती है कि स्वच्छ हवा के लिए उपलब्ध सीमित वित्तीय अनुदान का वितरण बेहद असमान है। वर्ष 2023 में फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65 फीसद बाहर से सहायता राशि मिली, जबकि उप-सहारा अफ्रीका के लिए सहायता

राशि 91 फीसद घट कर केवल 1.18 करोड़ डालर रह गई। यानी जिन इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा सबसे कमजोर है, वहीं मदद सबसे कम पहुंच रही है। इस मामले में बड़े देश किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, इसे समझा जा सकता है। प्रदूषण से लड़ने में गरीब देश अकेले पड़ते जा रहे हैं। भारत इस वैश्विक असमानता का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के शहर लगातार ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली, पटना, लखनऊ, कानपुर, धनबाद और गाजियाबाद ये नाम अब केवल शहर नहीं, बल्कि वैश्विक प्रदूषण की चेतावनी बन चुके हैं। सर्दियों के महीनों में उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा गैस चैंबर में बदल जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। भारत को स्वच्छ हवा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता में प्राथमिकता नहीं मिलती। न तो वायु प्रदूषण पर शोध के लिए पर्याप्त सहयोग मिलता है, न ही स्थानीय समाधान विकसित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश। जबकि भारत की स्थिति यह है कि यहां वायु प्रदूषण से हर साल करीब 95 अरब डालर की आर्थिक क्षति होती है।

> भारत जैसे देश के लिए वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है। यह गरीबी, असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीब बस्तियां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रहने वाले लोग, ये सभी सबसे अधिक प्रदूषण झेलते हैं। अगर वैश्विक वित्तीय सहायता जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं पर ही केंद्रित रही, तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा अभियान और धीमा पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, उद्योग और डीजल आधारित परिवहन न केवल जलवायु संकट को गहराएंगे, बल्कि भारत को एक स्थायी स्वास्थ्य आपदा की ओर भी धकेल देंगे।

यह नुकसान केवल अस्पतालों के बढ़ते खर्च में नहीं दिखता, बल्कि काम के दिनों की हानि, बच्चों के स्कूल न जा पाने, घटती उत्पादकता और जीवन की गिरती गुणवत्ता के रूप में सामने आता है। यह समस्या इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है। यह गरीबी, असमानता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। गरीब बस्तियां, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, सड़क किनारे रहने वाले लोग, ये सभी सबसे ज्यादा प्रदूषण झेलते हैं। मगर दुखद यह कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। अगर वैश्विक वित्तीय सहायता जीवाश्म ईंधन आधारित परियोजनाओं पर ही केंद्रित रही, तो भारत का स्वच्छ ऊर्जा अभियान धीमा पड़ेगा। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, डीजल आधारित परिवहन और प्रदूषण फैलाते उद्योग न केवल जलवायु संकट को गहराएंगे, बल्कि भारत को एक स्थायी स्वास्थ्य आपदा की ओर भी धकेल देंगे। यह भी समझना जरूरी है कि वायु प्रदूषण किसी एक देश तक सीमित नहीं रहता। यह सीमाओं के पार फैलता है।

दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल साझा वायु क्षेत्र में सांस लेते हैं। इसलिए वैश्विक वित्त की दिशाहीनता का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यह निराशाजनक है कि स्वच्छ पर्यावरण के पैरोकार देशों को ही चिंता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2040 तक मानव जनित वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि जी20 ने भी वायु गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मगर सच्चाई यह है कि वैश्विक राजनीति घोषणाओं में तो तेजी देखी जाती है, लेकिन संसाधन मुहैया कराने की प्रक्रिया बेहद धीमी है। जब तक नीतियों और बजट के बीच यह खाई बनी रहेगी, तब तक कोई भी लक्ष्य कागज से बाहर नहीं आ पाएगा।

'क्लीन एअर फंड' की रपट समाधान का रास्ता भी सुझाती है कि वित्त पोषण को जीवाश्म ईंधन के विस्तार से हटा कर स्वच्छ हवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ा जाए। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि मूल्यों का बदलाव है। यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी भी है। वायु प्रदूषण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह राजनीतिक फैसलों, आर्थिक प्राथमिकताओं का अभाव, इच्छाशक्ति की कमी और वैश्विक असमानता का परिणाम है। अगर विकास बैंक और वैश्विक संस्थाएं अब भी अपनी दिशा नहीं बदलतीं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और जी20 के लक्ष्य केवल खोखले घोषणापत्र बन कर रह जाएंगे, लेकिन अगर समय रहते दिशा बदली जाए, तो यह लड़ाई सिर्फ प्रदूषण की नहीं रहेगी, बल्कि न्याय, समानता और हर इंसान को स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के अधिकार की लड़ाई बन सकती है।